कांफ्रेंस कॉल ट्रांस्क्रिप्ट
06 अगस्त 2013

# "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

# तिमाही 1 वित्त वर्ष 14 कॉफ्रेंस कॉल"

## 06 अगस्त, 2013

**विश्लेषक : श्री समीर नारंग**

**प्रबंधन : श्री सतनाम सिंह- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

**श्री आर नागराजन- निदेशक (वित्त)**

कांफ्रेंस कॉल ट्रांस्क्रिप्ट
06 अगस्त 2013

**मॉडरेटर :** देवियों और सज्जनों, सुप्रभात। मैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा प्रायोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिमाही-1 वित्त वर्ष, 2014 की अर्निंग कांफ्रेंस कॉल में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कांफ्रेंस कॉल की अवधि के लिए अनुस्मारक के रूप में सभी प्रतिभागियों की लाइनें केवल लिशिन-ओनली मोड में होंगी। प्रेजेंटेशन पूरा होने पर आप सभी को अपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। यदि आपको इस कांफ्रेंस के दौरान किसी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है तो कृपया अपने टच फोन में "*" दबाने के बाद "0" दबाकर ऑपरेटर को संकेत करें। कृपया नोट करें कि इस कांफ्रेंस की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब मैं कांफ्रेंस के आगे के संचालन का दायित्व एचडीएफसी सिक्योरिटीज से श्री समीर नारंग को सौंपता हूं। धन्यवाद और श्री नारंग कृपया आगे आएं।

**श्री समीर नारंग:** धन्यवाद। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की ओर से मैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंधन विशेष रूप से श्री सतनाम सिंह, सीएमडी को परिणाम पश्चात इस कांफ्रेंस कॉल के आयोजन का हमें अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि महोदय इसकी शुरूआत हमें आपके उदबोधन से करनी चाहिए। तत्पश्चात हम प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करेंगे।

**सतनाम सिंह:** धन्यवाद, समीर। सबसे पहले मैं सभी निवेदशकों के बीच इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि भारतीय विद्युत क्षेत्र में मौजूदा चिंताओं का काफी हद तक समाधान कर लिया गया है। टैरिफ के संशोधन से संबंधित एक समस्या थी कि क्या राज्य टैरिफ वृद्धि को जारी रखेंगे अथवा नहीं और यदि आप 2013-14 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 29 राज्यों में से 24 राज्यों ने टैरिफ याचिका दायर कर दी है, जिनमें से 21 राज्यों ने टैरिफ वृद्धि (0% से 31% की रेंज में) की है, 3 राज्यों को अभी भी टैरिफ आदेश जारी करने हैं तथा 5 राज्यों विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में टैरिफ याचिका अभी दायर नहीं की गयी है।

एफआरपी चिंता का अन्य विषय है। 4 राज्यों ने अपने मंत्रीमंडल से इसे पहले ही अनुमोदित करा लिया है और 9 अन्य राज्यों ने भी अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। एफआरपी के लिए शर्तों में से एक शर्त यह है कि इस पर हस्ताक्षर हो

जाने के पश्चात बैंकों को पुन: ऋण प्रदान करना प्रारंभ करना होगा। तमिलनाडु के मामले में बैंकों ने ऋण देना शुरू कर दिया है और जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, बैंक शायद अन्य राज्यों को भी ऋण देना शुरू कर देंगे और इससे काफी हद तक इस मुद्दे का समाधान संभव हो सकेगा।

चिंता की अन्य बात यह थी कि यहां तक कि एफआरपी के पश्चात भी वितरण कंपनियों द्वारा ऋण की वसूली की समस्या बनी रहेगी। इस संबंध में आप सभी को अवगत कराया जाता है कि पीएफसी और आरईसी इस दिशा में आगे आए हैं और उन्होंने संक्रमणकालीन वित्तीय सहायता के रूप में अपेक्षाकृत अधिक दीर्घकालीन सहायता प्रदान की है। मैंने इस बात को पहले भी स्पष्ट किया है कि पीएफसी और आरईसी दोनों ने क्रमश: लगभग 18 हजार करोड़ और 17 हजार करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। पीएफसी ने 30-06-2013 तक 14818 करोड़ रूपए और तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 के दौरान 200 करोड़ रूपए का संवितरण किया है।

कोयले के मूल्य से संबंधित अन्य समस्या का भी समाधान किया गया। सीसीईए द्वारा आयातित कोयले के मूल्य की पूलिंग के संबंध में भी सहमति व्यक्त की गयी है और इस संबंध में केवल विशेष प्रावधान किए जाने हैं। गैस की समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव बाद में पता चलेगा। कोल इंडिया को भी 60000 मेगावाट क्षमता की तुलना में 78000 मेगावाट क्षमता के लिए पावर प्लांटों के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर करने के निदेश दिए गए हैं जिस पर पहले सहमति व्यक्त की गई थी।

मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) की बैठक में प्राकृतिक गैस की प्राथमिकता रैंकिंग के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा, जिसका आशय यह है कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बराबर प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र के लिए भी समान प्राथमिकता दी जाएगी और अंतिम रूप से मामला 1 और मामला 2 के लिए मानक बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया भी उन्नत चरण पर है । विद्युत मंत्रालय ने इन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया है और ऐसे संकेत दिए गए हैं कि मंत्रालय मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह से हो सकता है इस सप्ताह में अथवा अगले सप्ताह में पहल करे।

एक अन्य घटक जिसके संबंध में मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा, वह यह है कि आर-एपीडीआरपी योजना के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाए, जिसका उद्देश्य वितरण हानियों को कम करना है। सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के आधार पर क्रियान्वित घोषित किए जा रहे कस्बों की संख्या 31-03-2013 की स्थिति के अनुसार 169 से बढ़कर 30-06-2013 को 349 हो गई है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गत वर्ष प्राप्त की गई संख्या वर्तमान वर्ष में महज तीन माह में ही प्राप्त कर ली गई है और ऐसी आशा है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य अपने कस्बों में इसके कार्यान्वयन की घोषणा करेंगे। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक उपायों से भी हानियों को कम करने में सहायता मिलेगी। भाग-ख, जिसके अंतर्गत पारेषण और वितरण नेटवर्क का उन्नयन किया जाना है, से कमियों को कम करने में और सहायता मिलेगी, परंतु इसके कार्यान्वयन में अभी कुछ समय लगेगा। बड़ी संख्या में कस्बों को स्वीकृत किया गया है और कार्यान्वयन हेतु अधिनिर्णय किया गया है, इस प्रकार कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

इन सब कारणों से निवेशकों के बीच चिंता व्याप्त हो रही थी कि यदि विद्युत क्षेत्र में इन मुद्दों के संबंध में सरकार अपना पक्ष नहीं रखती है तो इनका क्या होगा। अब लगभग प्रत्येक मामले में हमें स्पष्ट जानकारी है, मेरा मानना है कि स्थितियां सही बनी रहेंगी। यह कहा गया है कि मुझे आप सभी के बीच तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 बनाम तिमाही 1 वित्त वर्ष 2013 के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों की चर्चा करनी चाहिए।

हमारी ऋण परिसंपत्तियां, जो हमारी आय का आधार हैं, 24% की वृद्धि के साथ 134,742 करोड़ रूपए से बढ़कर 167,196 करोड़ रूपए हो गई हैं। तदनुसार हमारी आय 27% की वृद्धि के साथ 3945 करोड़ रूपए से बढ़कर 5017 करोड़ रूपए हो गई है।

ब्याज से होने वाली निबल आया 39% की वृद्धि के साथ 1394 करोड़ रूपए से बढ़कर 1942 करोड़ रूपए हो गई है। हमारा विस्तार 66बीपीएस के साथ 2.63% से बढ़कर 3.29 % हो गया है। ब्याज का निबल मार्जिन 57 बीपीएस के साथ 4.19% से बढ़कर 4.76% हो गया है। कर पश्चात लाभ 23% की वृद्धि के साथ 972 करोड़ रूपए से बढ़कर 1198 करोड़ रूपए हो गया है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की है, यह लाभ संबंधी वास्तविक आंकड़ा नहीं हैं, बल्कि यह तुलनात्मक लाभ के आंकड़ें हैं जो निष्पादन के संदर्भ में उपयुक्त हैं। इस तिमाही के लिए तुलनात्मक लाभ 33% की वृद्धि के साथ

1029 करोड़ रूपए से बढ़कर 1365 करोड़ रूपए हो गया है।

पीएटी और तुलनात्मक पीएटी के बीच अंतर प्राथमिक रूप से तीन कारणों से है। सबसे पहले हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों का कार्यान्वयन शुरू किया है। 31 मार्च 2013 तक हमारी परिसंपत्तियों के लिए हम 3 वर्ष की अवधि हेतु 0.25% का प्रावधान करने जा रहे हैं। हालांकि उत्तरोत्तर बढ़ने वाली परिसंपत्तियों के लिए हम इन परिसंपत्तियों में वृद्धि के समतुल्य 0.25% का प्रावधान करने वाले हैं। इस मद में मानक परिसंपत्तियों के लिए 49 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

दूसरी बात यह है कि हमने लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार विनिमय हानि के ऋणमोचन का विकल्प चुना है। यद्यपि एमटीएम आधार पर विनिमय हानि की गणना 659 करोड़ रूपए के रूप में की जाएगी परंतु ऋणमोचित विनिमय हानि 109 करोड़ रूपए है। हो सकता है कि आपलोगों में से कुछ लोगों ने मेरे साथ पहले बातचीत करते हुए कुछ प्रश्न किए हों कि क्या ये सभी हानियां डॉलर के संबंध में हैं अथवा सभी मुद्राओं में हमें हानि हो रही है। इसका उत्तर यह है कि विदेशी मुद्रा में हमारा 29% ऋण जापानी येन (जेपीवाई) में हैं और जैसा आप सभी को ज्ञात है कि येन के अवमूल्यन से होने वाली हानि बहुत ही कम है।

तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 के दौरान यूएस डॉलर में 10% की हानि हुई है और जापानी येन के मामले में यह महज 5% है क्योंकि हमें यूएस डॉलर/जेपीवाई लैग में 5% का लाभ हुआ है और यद्यपि यूरो में यह हानि लगभग 13% है, परंतु बकाया राशि विदेशी मुद्रा में कुल ऋण की महज 2% है। अत: यदि आप पीएपी पर संपूर्ण प्रभाव पर नजर डालें, तो यह 109 करोड़ रूपए है, हालांकि एमटीएम आधार पर विनिमय हानि की गणना 659 करोड़ रूपए के रूप में की गई है।

तीसरी बात यह है कि वह घटक जिससे कर पश्चात लाभ और कर पश्चात तुलनात्मक लाभ प्रभावित होता है, वह विनिमय हानि के मद में आस्थिगित कर देयता से संबंधित है। लेखाओं के उद्देश्य से हम विनिमय संबंधी हानि की बुकिंग ऋणमोचन आधार पर कर रहे हैं; हालांकि कर के उद्देश्य से हम संपूर्ण हानि की बुकिंग कर रहे हैं और कर लाभ प्राप्त करने के लिए हम अपनी आस्थिगित कर देयता बढ़ा रहे हैं। हमारी कर की

औसत दर लगभग 30% है और आयकर विवरणी में हमारी कर दर लगभग 26% है। जहां तक विनिमय हानि के ऋणमोचित भाग का संबंध है, जिसे लाभ और हानि लेखे में बुक नहीं किया जा रहा है, के लिए आयकर अधिनियम के अनुसार हम 34% की अधिकतम दर पर आस्थिगित कर देयता सृजित कर रहे हैं (जिसके प्रभाव की गणना 43 करोड़ रूपए के रूप में की गई है)।

यदि इन तीन असाधारण मदों को हटा दिया गया, तो हमारा कर पश्चात तुलनात्मक लाभ तिमाही 1 वित्त वर्ष 2013 में 1029 करोड़ रूपए से बढ़कर तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 में 1365 करोड़ रूपए हो जाएगा।

अन्य घटक जिसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा, वह यह है कि इस तिमाही में एनपीए में कोई नया खाता नहीं जोड़ा गया है। हमारी सकल एनपीए 1.02% से घटकर 0.69% हो गई है और निबल एनपीए क्रमश: 30-06-2012 और 30-06-2013 की स्थिति के अनुसार 0.91% से 0.59% है। तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 के दौरान हमने कोना सीमा परियोजना के लिए 43 करोड़ रूपए (लगभग 10% का अतिरिक्त प्रावधान किया है), जिसे संदेहास्पद श्रेणी की परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है। 30-06-2013 की स्थिति के अनुसार जिन ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनमें श्री महेश्वर-700 करोड़ रूपए, कोनासीमा-414 करोड़ रूपए, एमपी पावर-27 करोड़ रूपए और ओम शक्ति- 9 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए समझौता ज्ञापन के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। स्वीकृतियों के लिए लक्ष्य 59000 करोड़ रूपए, संवितरण- 47000 करोड़ रूपए और संसाधन दोहन के लिए 44000 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एमओयू के ये सभी लक्ष्य आर-एपीडीआरपी के लक्ष्यों के अलावा हैं क्योंकि यह लगातार जारी रहने वाली योजना नहीं है और यहां तक कि इसके कार्यान्वयन में अभी समय लगेगा, लगभग सभी स्वीकृतियां पहले ही पूरी हो गयी हैं। इन लक्ष्यों की तुलना में तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 में निष्पादन इस प्रकार है: स्वीकृतियां- 15375 करोड़ रूपए (लक्ष्य का 26%), संवितरण- 8235 करोड़ रूपए (लक्ष्य का 18%) और संसाधनों का दोहन-9533 करोड़ रूपए (लक्ष्य का 22%)। बकाया स्वीकृतियां जिससे आप भावी वृद्धि दर का अनुमान लगा सकते हैं, 170,254 करोड़ रूपए है।

31-03-2013 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत पर्याप्तता 17.98% से बढ़कर 30-06-2013 की स्थिति के अनुसार 18.82% हो गई है। पूंजी पर्याप्तता में 84 बीपीएस का सुधार प्राथमिक रूप से 800 करोड़ रूपए के अतिरिक्त अधीनस्थ बांड जारी करने के परिणामस्वरूप हुआ है जो हमने तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 में 8.19% की दर से जारी किए । तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 में अधिकांश संसाधनों का दोहन 800 करोड़ रूपए के इन अधीनस्थ बांडों और 99 करोड़ रूपए की सीपी को छोड़कर नियमित बांडों के जरिए किया गया है।

जहां तक सहायक कंपनियों के निष्पादन का संबंध है, तो पीएफसी कंस्लटिंग लिमिटेड के पास 69 करोड़ रूपए मूल्य के 18 कार्य मौजूद हैं। तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 में तत्पश्चात लाभ 3.14 करोड़ रूपए है और आय 7.98 करोड़ रूपए है जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में कर पश्चात लाभ और आय क्रम: 16.38 करोड़ रूपए तथा 36.49 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार हम गत वर्ष के अनुरूप ही निष्पादन कर रहे हैं। विचाराधीन कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की आय में कुछ वृद्धि अवश्य होगी।

पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज एक नयी कंपनी है जिसे हमने सिंटिकेशन व्यवसाय के लिए स्थापित किया था। तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 में इसका कर पश्चात लाभ 0.83 करोड़ रूपए और आय 1.63 करोड़ रूपए है जबकि वित्त वष्र्ज़ 2013-14 में इसका कर पश्चात लाभ एवं आय क्रमश: 0.85 करोड़ रूपए और 1.78 करोड़ रूपए है। निश्चित ही हमने इसका प्रचालन गत वर्ष की शुरूआत से ही नहीं किया था।

पीएफसी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड के लिए हमने 1000 करोड़ रूपए की लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एएफडी फ्रांस के साथ चर्चा की थी। एएफडी लचीली शर्तों पर ऋण प्रदान कर सकता है परंतु जब तक शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, हम इससे संबंधित विवरण आपको नहीं दे सकते हैं। हमने 40 करोड़ रूपए की इक्विटी पूंजी का भी निवेश किया है और इस छूट में 138 करोड़ रूपए की निष्पादन शेयर पूंजी शामिल है। तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 में कर पश्चात लाभ 2.13 करोड़ रूपए और आय 3.03 करोड़ रूपए है जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में यह क्रमश: 0.40 करोड़ रूपए और 0.57 करोड़ रूपए है। तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 के दौरान 56 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गयी जबकि 8 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की गई। इस प्रकार हम एक नयी

कंपनी की शुरूआत कर रहे हैं।

जहां तक आर-एपीडीआरपी का संबंध है, हमने भाग-क (सूचना प्रौद्योगिकी) के लिए 100%, भाग-क(एससीएडीए) के लिए 97% और भाग-ख के लिए 98% राशि स्वीकृत की है और भाग-क (आईटी) के लिए 44% राशि संवितरित की है। इसके अलावा इन सभी परियोजनाओं में भुगतान अंतिम छोर से किए गए हैं और भाग-क (एससीएडीए) में संवितरण -28% और भाग-ख में 44% है। आप यह जानकर खुश होंगे कि 1366 (98%) कस्बों के लिए रिंग फेंसिंग कर दी गई है, 1092 (77%) कस्बों के लिए बेसलाइन डेटा तैयार कर लिया गया है और 349 कस्बों में कार्यान्वयन घोषित कर दिया गया है।

इस समय अल्ट्रा मेगापावर परियोजनाओं के मामले में हम उड़ीसा और चेय्यूर परियोजनाओं के संबंध में उन्नत चरण पर हैं परंतु इनके संबंध में कार्रवाई मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात ही शुरू की जा सकती है। जहां तक स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं का संबंध है, तो हमने पहले ही चार स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली हैं और हमें मंत्रालय से पांच नयी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनकी प्रगति अलग-अलग चरणों पर हैं। चार आईटीपी के लिए आरएफक्यू जारी कर दिए गए हैं और एक आईटीपी के लिए काफी पहले आरएफक्यू जारी किया गया था जिसके रूझान 30-08-2013 तक अपेक्षित हैं।

विद्युत मंत्रालय ने पीएफसी को दो और आईटीपी- पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना और टांडा विस्तार के लिए एटीएस के संबंध में बोली प्रक्रिया समन्वयक भी नियुक्त किया है।

इस प्रकार यदि हम इन परिवर्तनों जो विद्युत क्षेत्र में घटित हुए हैं, को और तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 के परिणामों को विस्तार से देखें तो हम सुरक्षित ढंग से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमने पहली तिमाही में बेहतर निष्पादन किया है और इन परिवर्तनों के प्रभाव के बावजूद भी हमें आशा है कि भविष्य में भी हमारा बेहतर निष्पादन जारी रहेगा अथवा कम से कम आगामी तिमाही में हम बेहतर निष्पादन जारी रख सकेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

**मॉडरेटर:** धन्यवाद। प्रतिभागियों अब हम प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न जेएम फाइनेंसियल से अमय साथे की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**अमय साथे:** महोदय, मेरे तीन प्रश्न हैं। सुजलोन के अलावा इस तिमाही के दौरान और किन ऋणों का पुनर्गठन किया जाएगा?

**सतनाम सिंह:** तिमाही 1 वित्त वर्ष 2014 के दौरान 2998 करोड़ रूपए (सुजलोन को दिए गए 946 करोड़ रूपए के पुनर्गठन सहित) का पुनर्गठन किया गया है।

**अमय साथे:** बाकी का क्या होगा?

**सतनाम सिंह:** पुनर्गठित किए गए दो अन्य ऋणों में ओएनजीसी त्रिपुरा के लिए 1685 करोड़ रूपए और एमपी पावर के लिए 27 करोड़ रूपए शामिल हैं।

**अमय साथे:** ओएनजीसी त्रिपुरा के ऋण का पुनर्गठन किस कारण से किया गया?

**सतनाम सिंह:** विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋणों का पुनर्गठन मुख्यत: स्थापना में विलंब के कारण किया जाता है।

**अमय साथे:** दूसरा प्रश्न बैंकिंग स्टेक अधिगृहीत करने से संबंधित है, क्या इस दिशा में कोई विकास किया गया है?

**सतनाम सिंह:** जैसा आपको ज्ञात है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो गयी है और हमने किसी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। जहां तक स्टेट अधिगृहीत करने का संबंध है, तो हम वित्त मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ इस संबंध में पत्राचार कर रहे थे। हालांकि अभी तक वहां से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, अत: मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसा कुछ घटित होने वाला है।

**अमय साथे:** अंतिम प्रश्न, संक्रमण कालीन वित्तीय सहायता, जो हम वितरण कंपनियों को प्रदान कर रहे हैं, इसलिए क्या इस संबंध में ब्याज के भुगतान पर भी कोई मोरेटोरियम है?

**सतनाम सिंह:** ब्याज पर कोई मोरेटोरियम नहीं है, तीन वर्ष तक मोरेटोरियम का विकल्प केवल मूलधन पर दिया जाता है।

**अमय साथे:** परंतु उन्हें ऋणों पर ब्याज का भुगतान करते रहना होगा, क्या मैं सही हूं?

**सतनाम सिंह:** निश्चित ही, आप सही हैं।

**अमय साथे:** आप कहां ऐसा महसूस करते हैं कि आपका लाभ बढ़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में मैं सोचता हूं कि हम जीवन पर्यंत ही उच्चतर लाभ की स्थिति में हैं, अत: मैं यह नहीं सोचता हूं कि यह परंपरा बनाये रखने में कोई कठिनाई होगी, क्या मैं सही हूं?

**सतनाम सिंह:** प्रश्न इस बात से संबंधित है कि इस बात के बावजूद भी कि आरबीआई ने दरें बढ़ा दी हैं, वित्तीय बाजार की स्थिति कैसी रहेगी। इस मद में हमारी ऋण लागत के भी बढ़ने की संभावना है। हमारे यहां बढ़ी हुई ऋण लागत का बोझ ऋणकर्ता पर डालने की प्रणाली मौजूद है, परंतु मेरा मानना है कि हमारे उच्च मार्जिन के बावजूद भी हमसे इसे ऋणकर्ता पर डालने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और इसके परिणामस्वरूप इसमें कुछ आंशिक कमी हो सकती है। लागत बढ़ने से उत्तरोत्तर संवितरण ही प्रभावित होता है और ऋण परिसंपत्ति के संचित मूल्य की तुलना में उत्तरोत्तर संवितरण काफी अधिक होता है।

**अमय साथे:** बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से इतना ही।

**मॉडरेटर:** धन्यवाद। अगला प्रश्न बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस से सुनील कुमार की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**सुनील कुमार:** धन्यवाद। वर्तमान मुद्दों पर अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, इस तिमाही के दौरान लगभग 3000 करोड़ रूपए के पुनर्गठन के बारे में आपके द्वारा किए गए उल्लेख के संबंध में सभी विकास, जो विद्युत क्षेत्र में किए गए हैं, पर विचार करते हुए अपनी बात जारी रखना चाहता हूं। अपने आरंभिक उदबोधन में जैसा आपने उल्लेख किया है कि सकल एनपीए अथवा वर्ष के दौरान पुनर्गठित परिसंपत्तियों के संदर्भ में आपकी खाता बही में परिसंपत्ति गुणपवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**सतनाम सिंह:** मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि मैं आपको इस संबंध में अपना कोई दृष्टिकोण बता सकता हूं। मैंने आपको उन सभी प्रयासों के बारे में जानकारी दी है, जो इस क्षेत्र में किए गए हैं और उनका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, अत: मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि मैं इस बात का पूर्वानुमान लगा सकता हूं कि आनेवाले समय में गुणवत्ता में सुधार होगा। मैं एक बात दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि जो परिवर्तन हुए हैं, उनका प्रभाव निश्चित ही सकारात्मक होगा। यदि कोई भी विकासकर्ता प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होता है, तो यह किसी अन्य घटक के कारण होगा न कि इन परिवर्तनों के कारण, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है।

**सुनील कुमार:** मुझे विश्वास है कि ईंधन, चाहे गैस हो अथवा कोयला, की उपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं की स्थापना में कुछ देरी अवश्य हो सकती है, जिनका जिक्र खाताबही में किया गया है। अत: इस परिप्रेक्ष्य से मैं केवल इतना समझना चाहता हूं कि आनेवाले वर्षों में आप कितने ऋणों का पुनर्गठन करेंगे?

**सतनाम सिंह:** ठीक है, जहां तक ज्यादातर विद्युत परियोजनाओं का संबंध है, उन्हें पीएलएफ स्तर पर प्रचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जो ऋणों की वसूली के लिए पर्याप्त है। मुद्दा यह है कि कुछ वितरण कंपनियां इन विकासकर्ताओं को भुगतान नहीं कर रही हैं, जिसके वित्तीय पुनर्गठन योजना के अंतिम कार्यान्वयन से समाधान होने की संभावना है और बैंकों ने वितरण कंपनियों को पुन: ऋण देना शुरू कर दिया है। मुद्दा यह है कि इन वितरण कंपनियों को निश्चित रूप से बड़ी राशि आवश्यक है, मैं राष्ट्रीय स्तर पर यह बात कह रहा हूं कि इसके लिए कम से कम 60000 से 70000 हजार करोड़ रूपए की कार्यशील पूंजी आवश्यक है, जो बैंकों से इस समय प्राप्त नहीं हो रही है, अत: एक बार अगर बैंक ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं तो

मेरा मानना है कि विकासकर्ताओं को वितरण कंपनियों से भुगतान प्राप्त होने लगेगा और वे ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे।

**सुनील कुमार:** अभी थोड़ी देर पहले आप यह कह रहे थे कि कोयले की उपलब्धता आदि से बड़ा मुद्दा राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यशील पूंजी आवश्यकता होगी, जिसे बैंकों द्वारा वित्त पोषण से पूरा करने की आवश्यकता है, क्या मैं सही हूं?

**सतनाम सिंह:** हां, यह ठीक है।

**सुनील कुमार:** वास्तव में यह मेरा दूसरा प्रश्न था कि यदि आप एनएचपीसी अथवा एनटीपीसी आदि जैसी कंपनियों के परिणामों पर नजर डालें तो हर व्यक्ति यही शिकायत करता है कि या तो राज्य विद्युत बोर्ड भुगतान नहीं कर रहे हैं अथवा वे पीछे हट रहें हैं, क्योंकि वे यहां तक कि थोड़ी सी महंगी बिजली भी नहीं चाहते हैं, अत: आप क्या सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा?

**सतनाम सिंह:** यह प्रश्न आपको एनएचपीसी अथवा एनटीपीसी से पूछना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

**सुनील कुमार:** विद्युत क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में एसईबी और एफआरपी, जिनके बारे में हम काफी लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं, वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जिनका मैंने जिक्र किया है, परंतु विद्युत क्षेत्र में आपकी जो सहभागिता है, मैं केवल उसे समझना चाहता हूं, साथ ही क्या आप हमें इस एफआरपी के कार्यान्वयन के समय के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं?

**सतनाम सिंह:** मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि 4 राज्यों ने अपनी संगत राज्य सरकारों से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और 9 राज्यों ने इसके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है और अब शेष कार्रवाई बैंकर और राज्य विद्युत बोर्ड की कंपनियों के बीच की जानी है। तीन कदम उठाये जाने हैं, बैंकों को 50% तक ऋण के बजाय वितरण कंपनियों द्वारा दिए गए बांडों को स्वीकार करना है, शेष 50% का नकदी

प्रवाह के आधार पर बैंक द्वारा पुनर्गठन किया जाना है और बैंकों को हानियों के निधियन हेतु पुन: ऋण देना प्रारंभ करना होगा। इस प्रकार मैं सोचता हूं कि अब गेंद बैंकों के पाले में है।

**सुनील कुमार:** महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**मुदित पनुली:** अन्य बात संक्रमण कालीन वित्त पोषण से संबंधित है, संक्रमण कालीन वित्त पोषण के मामले में वर्तमान में आपकी बकाया राशि क्या है?

**सतनाम सिंह:** संक्रमण कालीन वित्त पोषण के अंतर्गत 30-06-2013 की स्थिति के अनुसार हमने 14818 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की है और शर्तों के अनुसार मोरिटोरियम के पश्चात पुनर्भुगतान शुरू किया जाना चाहिए।

**मुदित पनुली:** इस संबंध में 15000 करोड़ रूपए का विषम आंकड़ा, 14800 करोड़ रूपए की बकाया स्वीकृतियां बाकी हैं, इस प्रकार कुल राशि कितनी होगी?

**सतनाम सिंह:** संक्रमण कालीन वित्त पोषण के अंतर्गत कुल स्वीकृतियां 18188 करोड़ रूपए और संवितरण 148181 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की गई।

**मुदित पनुली:** महोदय, इस संक्रमण कालीन वित्त पोषण पर आपकी सामान्य ऋण दर और अनुमानित दर के बीच क्या अंतर होगा?

**सतनाम सिंह:** हमने सामान्य ऋण और संक्रमण कालीन वित्त पोषण के लिए दरों में कोई अंतर नहीं किया है, बल्कि दर उस श्रेणी के आधार पर परिवर्तित होती है जिसमें विशेष रूप से कंपनी शामिल होती है और इसके लिए प्रतिभूति पर भी विचार किया जाता है। संक्रमण कालीन वित्तीय सहायता के मामले में सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है जिसके लिए दर 25 बीपीएस कम होती है। इसी कारण से दर परिवतर्तित होती है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्य क्षेत्र की किसी कंपनी से हम जो प्रभार वसूल करते हैं वह सुरक्षा पर निर्भर करता है, परंतु इस मामले में

राज्य सरकार की गारंटी के कारण 25 बीपीएस की कम दर का प्रावधान किया गया है। अत: मौजूदा मानक प्रक्रिया के आधार पर छूट प्रदान की गई है।

**मुदित पनुली:** अन्य बात पुनर्गठन से संबंधित है, क्या इस पुनर्गठन के अलावा भी भुगतान की कोई अनुसूची पुन: तैयार की गई है, जो आप आधारभूत ढंग से करते हैं, क्या कुछ महीने अथवा उसके पहले से भुगतान की कोई अनुसूची पुन: तैयार की गई है?

**सतनाम सिंह:** हमारे द्वारा पुन: तैयार की गयी कोई अनुसूची आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार होती है और मुझे विश्वास है कि आपको ज्ञात होगा कि जहां तक राज्य क्षेत्र का संबंध है तो इसके लिए हम छूट प्रदान करते हैं।

**मुदित पनुली:** वर्तमान में कुल बकाया पुनर्गठन की राशि कितनी होगी?

**सतनाम सिंह:** यह लगभग 10000 करोड़ रूपए है।

**मुदित पनुली:** धन्यवाद।

**मॉडरेटर:** धन्यवाद। अगला प्रश्न इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से जय प्रकाश तोशनीवाल की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**जय प्रकाश तोशनीवाल:** महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि अगले 18 माह में ऋणकर्ताओं से आपको कितना पुनर्भुगतान प्राप्त हो सकता है, कृपया मूलधन की राशि भी बतायें?

**सतनाम सिंह:** वित्त वर्ष 2013-14 के बकाया नौ माहों के लिए ऋण परिसंपत्ति से होने वाली कुल प्राप्तियां (मूलधन की राशि) 10943 करोड़ रूपए है।

**जय प्रकाश** अगले वित्त वर्ष अर्थात 2015 के लिए यह राशि कितनी होगी?

**तोशनीवाल:**

**सतनाम सिंह:** लगभग 12000 करोड़ रूपए ।

**जय प्रकाश तोशनीवाल:** निजी क्षेत्र के लिए आपके बकाया ऋण घटक, जो कि अनुमानत: लगभग 21400 करोड़ रूपए है, से कितनी परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है, अगले दो वर्ष में कितनी परियोजनाओं की स्थापना किए जाने की अपेक्षा है?

**सतनाम सिंह:** निदेशक (वित्त) इस प्रश्न का उत्तर देंगे।

**आर नागराजन:** निजी क्षेत्र की उत्पादन परियोजनाओं को 19999 करोड़ रूपए की कुल बकाया राशि में से 4857 करोड़ रूपए ऐसी परियोजनाओं के लिए है, जिनकी स्थापना की जा चुकी है, 8653 करोड़ रूपए उन परियोजनाओं से संबंधित है, जिनके वित्त वर्ष 2013-14 की बकाया अवधि में स्थापित किए जाने की अपेक्षा है, 6423 करोड़ रूपए ऐसी परियोजनाओं के संबंध में है, जिनकी स्थापना वित्त वर्ष 2014-15 में होने की आशा है और 66 करोड़ रूपए ऐसी परियोजनाओं से संबंधित है, जिनकी स्थापना वित्त वर्ष 2015-16 में किया जाना अपेक्षित है।

**जय प्रकाश तोशनीवाल:** धन्यवाद।

**मॉडरेटर:** धन्यवाद। अगला प्रश्न मल्टी एक्ट से रोहन सामंत की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**रोहन सामंत:** महोदय, मेरा प्रश्न उस प्रतिशत से संबंधित है, जो परियोजनाओं की स्थापना में विलंब के कारण प्रभावित होती हैं और कितने प्रतिशत परियोजनाओं की स्थापना में अक्षमता के कारण विलंब होता है जैसा सुजलोन के मामले में हुआ है, वे भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, क्या इस पर प्रकाश डालेंगे?

**सतनाम सिंह:** स्थापना में विलंब के कारण 8832 करोड़ रूपए के ऋणों का पुनर्गठन किया गया। अर्थात इन ऋणों के मामले में पुनर्भुगतान पुन: तैयार की गयी अनुसूची के समय से शुरू नहीं किया गया था; इसके अलावा परियोजना की स्थापना में विलंब के कारण पुनर्भुगतान को आगे बढ़ा दिया गया है। कुछ ऋणकर्ताओं के मामले में, पुनर्भुगतान शुरू कर दिया गया था; हालांकि तरलता संबंधी समस्या के चलते इस बीच हुए भुगतान नहीं कर सके और उन्होंने पुनर्गठन के लिए हमसे अनुरोध किया। स्थापना में विलंब से इतर अन्य कारणों से पुन: अनुसूचित ऐसे ऋणों की राशि 1314 करोड़ रूपए है। 1314 करोड़ रूपए के विवरण इस प्रकार हैं: सुजलोन- 946 करोड़ रूपए, उड़ीसा पावर कंसोर्टियम- 51 करोड़ रूपए, एमपी पावर कंपनी- 27 करोड़ रूपए और इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉय- 289 करोड़ रूपए।

**रोहन सामंत:** धन्यवाद।

**मॉडरेटर:** धन्यवाद। अगला प्रश्न एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग से दिगंत हरिया की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**दिगंत हरिया:** अभी ठीक पहले आपकी टिप्पणियों को सुन रहा था, आप और आरईसी ने मिलकर संक्रमतण कालीन वित्त पोषण के लिए लगभग 36000 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है और मैं देख रहा हूं कि इनमें से ज्यादातर संवितरण पहले ही कर दिया गया है। इस प्रकार अगली एक अथवा दो तिमाही में यदि बैंक राज्य विद्युत बोर्डों को ऋण देना शुरू नहीं करते हैं, क्या हम अपनी स्वीकृतियां बढ़ायेंगे और क्या हम उन्हें और ऋण देना जारी रखेंगे, क्या हम पीएफसी और आरईसी के लिए अलग-अलग 18000 करोड़ रूपए पर ही स्वीकृतियां बंद कर देंगे?

**सतनाम सिंह:** इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**दिगंत हरिया:** अभी के लिए यह रहेगा, इस बात का अनुमान लगाना सुरक्षित होगा कि आपने अपनी बोली लगा दी है और अब बैंकों को अपनी बोली लगाने के लिए आगे आना है। संक्रमण

कालीन इस वित्त पोषण को हम इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं कि 10 वर्ष की अवधि के लिए ऋण अथवा हमारे एएलएम में आप इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं।

**सतनाम सिंह:** पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की राशि वार्षिक बुकलेट में दर्शायी जाएगी और 3 वर्ष के पश्चात मूलधन और ब्याज दोनों ही वर्षवार बुकलेट में दर्शाये जाएंगे।

**दिगंत हरिया:** परंतु संपूर्ण अवधि 10 वर्ष ही होगी, क्या मैं सही हूं?

**सतनाम सिंह:** ब्याज के भुगतान हेतु अवधि 10 वर्ष है और मूलधन के लिए 7 वर्ष।

**दिगंत हरिया:** मेरी ओर से इतना ही। आपका धन्यवाद।

**मॉटरेटर:** धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न मैक्वायर से सुरेश गणपति की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**सुरेश गणपति:** मैं केवल दो बातें जानना चाहता हूं; सबसे पहले क्या इन किसी भी पुनर्गठन पर आपको कोई एनपीवी हानि हुई है अथवा आपने इसके लिए कोई प्रावधान किया है?

**सतनाम सिंह:** कोई हानि स्वीकार नहीं की गई है।

**सुरेश गणपति:** इस प्रकार समेकित रूप से 10000 करोड़ रूपए का आंकड़ा है जो लगभग स्थापना में विलंब के कारण 8800 करोड़ रूपए और अन्य कारणों से 1300 करोड़ रूपए के रूप में है, यह कोई एनपीवी हानि नहीं है और इसके लिए केवल 25 आधारभूत बिंदुओं का प्रावधान किया जाएगा अथवा 3 वर्ष की अवधि के पश्चात ही ऐसा किया जाएगा, क्या मैं सही हूं?

**सतनाम सिंह:** जी, हां।

**सुरेश गणपति:** इस 8800 करोड़ रूपए के संबंध में एक और अन्य बात, आपने ओएनजीसी त्रिपुरा के विभाजन के संबंध में 3000 करोड़ रूपए दिए और अन्य व्यय जैसे सुजलोन के संबंध में क्या यह कहना संभव है कि इस 8800 करोड़ रूपए में 300 करोड़ रूपए के विभाजन के अलावा ऐसी कोई अन्य बड़ी परिसंपत्ति शामिल है, जो आपने शेष 500 करोड़ रूपए के लिए दी है?

**सतनाम सिंह:** ऐसे अन्य ऋण जिनकी अनुसूची पुन: तैयार की गई है, उनमें लैंको अमरकंटक पावर, केवीके नीलांचल, सासन पावर के साथ-साथ कुछ एनपीए खाते जैसे कोना सीमा गैस और पावर और श्री महेश्वर हाइड्रल पावर शामिल हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि परियोजना की स्थापना में यहां तक कि 3 माह का भी विलंब होता है और हम भुगतान को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करते हैं तो हम इसे भुगतान का पुनर्अनुसूचीयन मानेंगे। यही कारण है कि हमने उन परियोजनाओं को पुनर्भुगतान (8832 करोड़ रूपए) की अनुसूची के रूप में वर्गीकृत किया है, जिनसे स्थापना में विलंब के कारण समय पर भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है और जिन मामलों में तरलता की कमी आदि जैसे विभिन्न कारणों से आगे भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है, उसमें 13314 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

**सुरेश गणपति:** इस एनपीवी हानि के संबंध में एक बात मैं बेहतर ढंग से समझना चाहता हूं, मेरा आशय यह है कि इस तथ्य के बावजूद भी कि आप पुन: अनुसूचीयन कर रहे हैं और इसमें कठिनाई हो रही है, जो कुछ भी किया गया है, इसका शून्य एनपीवी हानि पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा आशय यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी राशि होनी चाहिए, जो खो जाती है, क्या इस प्रक्रिया के लिए मेरा यह तर्क सही है?

**सतनाम सिंह:** यहां तक कि एक आधारभूत बिंदु की कमी का भी प्रावधान नहीं है और हम उनके द्वारा देय ब्याज पर भी समान दर से ब्याज वसूल कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ ऋणों, जिनके लिए हमने ब्याज के संबंध में निधियन किया है, यहां तक कि उनमें भी हम सामान्य ब्याज दर से ही वसूली कर रहे हैं। जहां तक दोनों ब्याज दरों का संबंध है, तो यह लगभग 12.5% है। अत: सबसे पहले एफआईटीएल करते हैं, फिर उस मद में हम लगभग 12.5% की दर से ब्याज वसूल करते हैं, अत: एनपीवी हानि का प्रश्न ही

नहीं उठता है।

**सुरेश गणपति:** मैं समझ गया। मैं केवल इसकी प्रक्रिया जानना चाहता था। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। अगला प्रश्न एक्वायरस सिक्योरिटीज से देवांग मोदी की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**देवांग मोदी:** महोदय, अच्छे आंकड़ों के लिए बधाई। महोदय, आपने पहले इस बात का उल्लेख किया था कि गैस के संबंध में कुछ कार्रवाई शुरू की जा रही है, परंतु मुद्दे के समाधान में कुछ समय लग सकता है, अत: आपने जिस कार्रवाई का संदर्भ दिया था, किस संबंध में शुरू की गई है?

**सतनाम सिंह:** मूल्य संबंधी मुद्दे पर चर्चा की गई है, अगले वर्ष के अप्रैल माह से मूल्य बढ़ जाएगा। इसके अलावा पुरानी प्राथमिकता समाप्त हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र को तदनुसार समान प्राथमिकता दी जाएगी।

**देवांग मोदी:** जी हां, अत: मुख्य रूप से वे दो बातें, गैस का मूल्य निर्धारण और सामान्य प्राथमिकता संभवत: जून से प्रदान की जाएगी। महोदय, मैं यह भी समझना चाहता हूं कि परिसंपत्तियों के संदर्भ में हमारे संपूर्ण पोर्टफोलियो का प्रचालनात्मक प्रतिशत क्या है, जिनका हमने वित्त पोषण किया है और इसकी समतुल्य राशि क्या होगी?

**आर नागराजन:** 30-06-2013 की स्थिति के अनुसार स्थापित परियोजनाओं की बकाया राशि 41583 करोड़ रूपए है।

**देवांग मोदी:** ठीक है और महोदय वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2015 में हमारे अनुमान के अनुसार हमारे पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत प्रचालनरत होने की अपेक्षा है?

**सतनाम सिंह:** वित्त वर्ष 2013-14 की शेष अवधि में हमें आशा है कि 50620 करोड़ रूपए की परियोजनाएं स्थापित होंगी और वित्त वर्ष 2014-15 में यह 21732 करोड़ रूपए होना

चाहिए।

**देवांग मोदी:** अत: वित्त वर्ष 2014 में यह 50000 करोड़ रूपए है। अत: क्या यह लगभग 20000 मेगावाट से भी अधिक के समतुल्य होगा?

**आर नागराजन:** मेगावाट के संदर्भ में 30-06-2013 की स्थिति के अनुसार स्थापित परियोजनाओं की क्षमता 30560 मेगावाट है और वित्त वर्ष 2013-14 की शेष अवधि में हमें आशा है कि 24653 मेगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी। वित्त वर्ष 2014-15 में 23438 मेगावाट और वित्त वर्ष 2015-16 में 645 मेगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी।

**देवांग मोदी:** वित्त वर्ष 2014 की इस राशि के संबंध में एक प्रश्न। क्या मैं सही हूं कि यह आंकड़ा 50620 करोड़ रूपए है? महोदय, मार्जिन की दृष्टि से हमने पहले ही मार्गदर्शन किया है कि हमारा मार्जिन कम हो सकता है जबकि हमारी लागत बढ़ जाएगी, क्या आप पूरी बात नहीं बताना चाहते हैं?

**सतनाम सिंह:** चूंकि हमारा मार्जिन काफी अधिक है, अत: हमें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हम बढ़ी हुई ऋण लागत का बोझ ऋणकर्ता पर डालें। हालांकि इसका आशय यह नहीं है कि हमारा लाभ कम हो जाएगा। अत: पहली बात यह है कि कितनी लागत अधिक होगी। प्रश्न भी इससे ही संबंधित है, इसका निर्धारण वित्तीय बाजार ही करेगा। दूसरी बात यह है कि यह केवल उत्तरोत्तर संवितरण पर ही लागू होता है, जो किसी विशेष तिमाही में कुल ऋण बही के बहुत ही कम प्रतिशत के बराबर होता है। तीसरी बात यह है कि हमारी संरचना ऐसी नहीं है जिसमें प्रत्येक वृद्धि को ऋणकर्ता पर डाल दिया जाये। माना कि हम पहले से ही बेहतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हमारी ऋण संरचना में हम ब्याज दरें नहीं बढ़ा सकते हैं, अत: मैंने इस बात का उल्लेख किया कि इसका केवल आंशिक प्रभाव ही हो सकता है।

**देवांग मोदी:** ठीक है, महोदय मैं समझ गया। महोदय, आपका धन्यवाद। मेरी ओर से इतना ही।

**मॉडरेटर:** धन्यवाद। अगला प्रश्न बारक्लेस से जतिन मुमतानी की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**जतिन मुमतानी :** मेरा प्रश्न स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न गैस की उपलब्धता से संबंधित है, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस संबंध में

जानकारी दे सकते हैं कि निजी क्षेत्र की गैस पावर परियोजनाओं के संबंध में बकाया ऋण कितना है?

**सतनाम सिंह:** गैस पावर परियोजनाओं को स्वीकृत ऋणों की बकाया राशि 7471 करोड़ रूपए है।

**जतिन मुमतानी :** इसमें से निजी क्षेत्र के लिए कितना है?

**सतनाम सिंह:** निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी में 3236 करोड़ रु. है (जिसमें ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी का 2024 करोड़ रुपए शामिल है)।

**जतिन मुमतानी :** ओएनजीसी त्रिपुरा की स्थापना में विलंब है, इसकी शेष यूनिट निर्माणाधीन है, क्या ऐसा है?

**सतनाम सिंह:** ओएनजीसी त्रिपुरा के अलावा अन्य सभी परियोजनाओं की स्थापना कर ली गई है।

**जतिन मुमतानी :** मेरा दूसरा प्रश्न ऋण वृद्धि से संबंधित था, इस प्रकार ऋण वृद्धि काफी बेहतर रही है और आपने इसे 23% से 24% के स्तर पर बनाए रखा है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि अगले वर्ष दौरान इसमें थोड़ा कमी हो सकती है और या इस संबंध में कोई व्यापक मार्गदर्शन किया गया है अथवा क्या आप इस संबंध में कोई मार्गदर्शन देना चाहेंगे?

**सतनाम सिंह :** नहीं, आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि हम व्यापक मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं परंतु आपको ऐसे घटकों के आधार पर अपना हस्तक्षेप कम करना होगा जिनकी जानकारी मैंने आपको दी है और जिनका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। समझौता ज्ञापन के जो लक्ष्य हमें दिए गए हैं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विकासकर्ताओं की क्षमता और योग्यता तथा बकाया स्वीकृतियां लगभग 1.70 लाख करोड़ रु. हैं।

**जतिन मुमतानी :** इससे बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। अगला प्रश्न आईआईएफएल से अभिषेक मुरारका की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**अभिषेक मुरारका :** मेरा प्रश्न केवल डेटा संग्रहण से संबंधित है। वर्ष के शेष भाग में परिसंपत्तियों और देनदारियों की कितनी राशि का पुनर्निर्धारण, ब्याज दर का पुनर्निर्धारण किया जाएगा?

**सतनाम सिंह :** वित्त वर्ष 2013-14 की शेष अवधि में पुनर्निर्धारण के लिए बकाया परिसंपत्तियां 21230 करोड़ रुपए और देनदारियां 27486 करोड़ रुपए हैं।

**अभिषेक मुरारका :** महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न आपकी सभी गैस आधारित परियोजनाओं जिनके बारे में आपने चर्चा की है, से संबंधित है, क्या रत्नगिरि गैस परियोजना के लिए कोई एक्सपोजर दिया गया है?

**सतनाम सिंह :** हां, रत्नगिरि गैस परियोजना का बकाया ऋण 749 करोड़ रुपए है, परंतु इसके लिए राज्य सरकार की गारंटी उपलब्ध है।

**अभिषेक मुरारका :** इसकी क्या स्थिति है ? मेरा मानना है कि वहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि राज्य की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने उन्हें भुगतान नहीं किया है और हो सकता है कि वह इसे अपनी चूक बताए अथवा बाद में इसका भुगतान करे अथवा अन्य कोई बात है, वहां क्या स्थिति है?

**सतनाम सिंह :** आज की स्थिति के अनुसार वहां कोई बकाया राशि देय नहीं है।

**आर. नागराजन :** आज की तारीख के अनुसार उन्होंने सभी बकाया राशियों का भुगतान कर दिया है।

**अभिषेक मुरारका :** इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। अगला प्रश्न इ्यूस्ची बैंक से मोनिश शुक्ला की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**मोनिश शुक्ला :** महोदय, शुप्रभात। यदि 9 अन्य राज्य एफआरपी के लिए सहमत हो जाते हैं, तो क्या यह संभव है कि आप उन राज्यों को भी अतिरिक्त संक्रमणकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे?

**सतनाम सिंह :** मेरा मानना है कि हमने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है, मैं पुन: बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**मोनिश शुक्ला :** दूसरी बात यह है कि मुद्रा की अस्थिरता के बावजूद भी क्या आपके एफएक्स ऋणों की हैजिंग नीति के संदर्भ में कोई रणनीतिक परिवर्तन किया गया है?

**सतनाम सिंह :** हमने अपनी ब्याज दर के जोखिम को हैज करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, परंतु चूंकि हमारा कुल ऋण ही बहुत कम अर्थात संपूर्ण बकाया ऋण देयता का 6% है, अत: इस संबंध में हमें अधिक चिंता नहीं है। मैं यह नहीं कहूंगा कि हमें इस संबंध में कोई चिंता नहीं है, परंतु हम इस बारे में थोड़ा कम चिंतित हैं।

**मोनिश शुक्ला :** अत: लगभग 15% हैज कर लिया गया है, क्या मैं सही हूं, क्या अभी भी स्थिति उतनी ही है?

**सतनाम सिंह :** हां, 15% मूलधन हैज किया गया है और ब्याज दर 16% हैज की गई है।

**मोनिश शुक्ला :** ठीक है, अंत में मैं इस वर्ष के दौरान आपके द्वारा ऋण वृद्धि के बारे में जानना चाहता हूं क्या आप विदेशी मुद्रा में कोई ऋण लेने की योजना बना रहे हैं?

**सतनाम सिंह :** ठीक है, हमारा कुल लक्ष्य 44,000 करोड़ रुपए एकत्रित करने का है, जिसमें से हमने पहले ही लगभग 9500 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अब शुरुआत में हम यह निश्चय नहीं करते हैं कि हम यह राशि भारतीय मुद्रा अथवा विदेशी मुद्रा में जुटाने का प्रयास करेंगे। ऋण लेते समय, जब कभी भी हमें आवश्यकता होगी, हम विदेशी मुद्रा में ऋण की संपूर्ण हैजिंग लागत और घरेलू ऋण दर की तुलना करते हैं और हमारे लिए जो लाभप्रद होता है वह विकल्प चुनते हैं। अब यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि घरेलू दर क्या होगी। यदि घरेलू ब्याज दर बढ़ जाती है तो विदेशी मुद्रा में ऋण लिया जा सकता है, इस प्रकार हम विदेशी मुद्रा में ऋण ऐसी स्थितियों में ही लेते हैं अन्यथा हम घरेलू ऋण को प्राथमिकता देते हैं।

**मोनिश शुक्ला :** धन्यवाद। अगला प्रश्न बजाज फाइनेंस से स्वप्ना नाइक की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**स्वप्ना नाइक :** महोदय, वे घटक कौन से हैं, जिनके परिणामस्वरूप तिमाही के दौरान एनआईएमएस, मार्जिन आदि में सुधार हुआ है?

**सतनाम सिंह :** मार्जिन में सुधार के लिए उत्तरदायी घटकों के बारे में मैंने पहले भी स्पष्ट किया था। इसके लिए हम वर्ष दर वर्ष पुनर्मूल्यांकित की जा सकने वाली परिसंपत्तियों के साथ देनदारियों की तुलना करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कुछ समय पहले तक आरबीआई कभी भी ब्याज दरें बढ़ा रहा था और हम इस स्थिति में नहीं थे कि तुरंत ही बढ़ी हुई ब्याज दरों का बोझ हम ऋणकर्ताओं पर डाल सकें क्योंकि हमारी देयता का पुनर्मूल्यांकन तो आरबीआई द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा के साथ कर दिया जाता था; परंतु अब आरबीआई ने कभी भी ब्याज दरें बढ़ाना बंद कर दिया है, अत: अब हम उनकी तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा हर तिमाही में ऋण की काफी बड़ी राशि पर ब्याज दर का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तिमाही-1 वित्त वर्ष 2014 में पुनर्निर्धारण के मद में 63 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की गई और मुक्त आय में 24 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। मार्जिन में सुधार के लिए उत्तरदायी कारण यही हैं। इसके अलावा ऋण लागत में भी 23 आधारभूत बिन्दुओं की कमी से भी हमारा मार्जिन बढ़ा है।

कांफ्रेंस कॉल ट्रांस्क्रिप्ट
06 अगस्त 2013

**स्वप्ना नाइक :** महोदय, परिसंपत्तियों की मात्रा कितनी है, जिनका इस तिमाही के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गया है?

**सतनाम सिंह :** तिमाही-1 वित्त वर्ष 2014 के दौरान 7068 करोड़ रुपए (रुपए में लिया गया आवधिक ऋण) की परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण किया गया है।

**स्वप्ना नाइक :** महोदय, आपका धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। अगला प्रश्न इडलबीस से कुनाल शाह की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**कुनाल शाह :** महोदय, बधाई। ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। मेरा प्रश्न लैंको परियोजना से संबंधित था, जिसके बारे में हम मीडिया में पढ़ते रहे हैं। अत: इसके लिए एक्सपोजर क्या रहा है और लैंको के मामले में पुनर्गठन संबंधी किसी जोखिम की भी संभावना है क्या?

**सतनाम सिंह :** लैंकों परियोजना की बकाया ऋण राशि 2922 करोड़ रुपए है। इस मामले में कुछ विलंब हुआ है और यह विलंब इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दोनों से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि एफआरपी के कार्यान्वयन के बाद जब बैंक इन राज्यों को फिर से ऋण देना शुरू कर देंगे, तो यह समस्या हल हो जाएगी। मेरा मानना है कि यदि आप पिछले 60 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें, तो किसी भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा खरीदी गई किसी यूनिट का भुगतान कुछ देरी से किया गया है।

**कुनाल शाह :** महोदय, यह राशि तो 2922 करोड़ रु. है, उडुप्पी, अमरकंटक आदि के मामले में वर्तमान में इसका क्या स्तर है?

**सतनाम सिंह :** श्री कुनाल जहां तक मुझे ज्ञात है कि लैंको इन्फ्राटेक के लिए हमने कोई एक्सपोजर नहीं दिया है। उडुप्पी पावर और लैंको अमरकंटक पावर की ऋण राशि बकाया है, जो

लैंको इन्फ्रटेक की सहायक कंपनियां हैं। हालांकि, सीडीआर पर पुनर्गठन केवल लैंको इन्फ्राटेक के लिए ही किया जा रहा है और हमें लैंको इन्फ्राटेक के लिए कोई एक्सपोजर प्राप्त नहीं हुआ है।

**कुनाल शाह :** क्या अमरकंटक के मामले में ऐसा पहले ही कर लिया गया है?

**सतनाम सिंह :** अमरकंटक के मामले में इसकी यूनिट-I और II की स्थापना पहले ही कर ली गई और यहां तक कि यूनिट-III और IV भी निर्माणाधीन है। उडुप्पी की स्थापना कर ली गई है और उडुप्पी का टैरिफ बढ़ाने के लिए सीईआरसी द्वारा 20.8.2013 को सुनवाई आयोजित की जा रही है। अमरकंटक के मामले में टैरिफ बढ़ाने के लिए सुनवाई हरियाणा में पिछले सप्ताह आयोजित की गई और ऐसा हो जाने के पश्चात उन्हें लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो सकती है। उडुप्पी के मामले में उन्हें कर्नाटक की वितरण कंपनियों से आंशिक धनराशि प्राप्त हो सकती है।

**कुनाल शाह :** यह राशि 2900 करोड़ रुपए है, जिसके बारे में आपने यह उल्लेख किया था कि इसका पुनर्गठन तिमाही-1 में ही किया गया, ओएनजीसी त्रिपुरा के मामले में ऐसा कब किया गया?

**सतनाम सिंह :** श्री कुनाल मैं आपको पुन: अवगत कराना चाहता हूं कि विश्लेषक की परिभाषा के अनुसार ओएनजीसी त्रिपुरा के पुनर्गठन को आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि उसका पुनर्गठन स्थापना में विलंब के कारण किया गया है। मुख्य रूप से सुजलोन ऐसा मामला है जहां उन्होंने पुन: भुगतान किया है और इसी बीच इसका पुनर्गठन किया गया है। इस प्रकार विश्लेषक के दृष्टिकोण से हमारी पुनर्गठित परिसंपत्ति केवल 1314 करोड़ रुपए है। यह पुनर्गठन स्थापना की तारीख को आगे बढ़ाए जाने से हुआ है और इस मामले में 8832 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इस प्रकार आपकी सूचना के लिए केवल 1314 करोड़ रु. को ही शामिल करने की आवश्यकता है।

**कुनाल शाह :** हम इसकी जानकारी नकदी प्रवाह के मुद्दे के लिए लेना चाहते हैं। परंतु ओएनजीसी त्रिपुरा के मामले में क्या यह इसी तिमाही में घटित हुआ है अथवा माजरा क्या है?

**सतनाम सिंह :** ओएनजीसी, त्रिपुरा का पुनर्गठन तिमाही-1 वित्त वर्ष 2014 में किया गया। उन्होंने एक यूनिट की स्थापना पहले ही कर ली है और मेरा मानना है कि दिसंबर, 2013 तक एक और यूनिट की भी स्थापना हो जाएगी।

**कुनाल शाह :** महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। अगला प्रश्न एक्वायरस सिक्योरिटीज से देवांग मोदी की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**देवांग मोदी :** मेरा प्रश्न 50620 करोड़ रुपए की राशि से संबंधित है, जिसे अन्य लोगों द्वारा पहले भी पूछा गया है, जिसका उल्लेख आपने किया था कि वित्त वर्ष 2014 की शेष अवधि में इसकी स्थापना की जाएगी। राज्यों, केन्द्र और निजी क्षेत्रों के बीच इसका विभाजन किस प्रकार किया गया है?

**सतनाम सिंह :** राज्य और केन्द्र क्षेत्र की हिस्सेदारी 41968 करोड़ (12,930 मेगावाट) और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 8653 करोड़ रुपए (11,723 मेगावाट) है।

**देवांग मोदी :** महोदय, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। अगला प्रश्न आईआईएफएल से अभिषेक मुरारका की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**अभिषेक मुरारका :** महोदय, मेरा अन्य प्रश्न वृद्धि दर से संबंधित है। महोदय, आपके द्वारा दिए गए प्रजेंटेशन से मैं जो समझता हूं कि वर्तमान संवितरण अथवा आहरण बकाया स्वीकृतियों के लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा? कुल बकाया स्वीकृतियां लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए की हैं, परंतु मध्यवर्ती संवितरण संभवत: ऐसे ऋणकर्ताओं को किया जाएगा, जिनके दस्तावेज निष्पादित हो गए हैं, क्या संवितरण शूरू कर दिया गया है अथवा आगे किया जाएगा? इस प्रकार यह राशि मुख्य रूप से लगभग 100,000 करोड़ रुपए अथवा उसके आसपास होगी। इस प्रकार क्या आप यह महसूस करते हैं कि वर्तमान वर्ष में इन बकाया स्वीकृतियों से आर-एपीडीआरपी संवितरण को छोड़कर आप

अपने 47,000 करोड़ रुपए के संवितरण का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे?

**सतनाम सिंह :** यह हमारा समझौता ज्ञापन का लक्ष्य है और हमें इसे अवश्य प्राप्त करना है।

**अभिषेक मुरारका :** यह गिरावट के संकेत देते हैं क्या आप पहले से मौजूदा और प्रस्तावित प्रस्तावों में ऐसा महसूस नहीं करते हैं?

**सतनाम सिंह :** हां।

**अभिषेक मुरारका :** धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। अगला प्रश्न स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज से निखिल रूंगटा की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

**महरुख :** महोदय, नमस्कार। मैं महरुख। मैंने लैंको पर आपकी फीडबैक को अवश्य सुना था। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि पुनर्गठन में कौन सी परियोजनाओं को शामिल किया गया है? क्या ऐसी सभी परियोजनाओं का पुनर्गठन किया है, जिनके लिए आपको एक्सपोजर मिला हुआ है?

**सतनाम सिंह :** उडुप्पी के मामले में 1325 करोड़ की बकाया ऋण राशि में से 491 करोड़ रुपए की राशि का पुनर्गठन किया गया है और लैंको अमर कंटक के मामले में 1429 करोड़ रुपए की बकाया ऋण राशि में से 447 करोड़ रुपए की राशि का पुनर्गठन किया गया है।

**महरुख :** महोदय, ठीक है और इनका पुनर्गठन कब किया गया?

**सतनाम सिंह :** लैंको अमरकंटक का पुनर्गठन अप्रैल, 2010 में और उडुप्पी का जनवरी, 2011 में किया

गया है।

**महरुख :** महोदय, ठीक है। क्या ये पुनर्गठन के अनुसार निष्पादन कर रही हैं? मुझे ज्ञात है कि आपने एसईबी की वृद्धि के बारे में चर्चा की थी परंतु यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा?

**सतनाम सिंह :** प्रश्न ही नहीं उठता है कि ऐसा न हो। यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। टैरिफ बढ़ाए जाने से एसईबी के राजस्व में वृद्धि होती है। एफआरपी को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है कि ऋण की वसूली में कोई समस्या न हो। बैंकों को पुन: ऋण देना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू करना होगा कि भविष्य में कोई समस्या न हो और इस मुद्दे के समाधान के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

**महरुख :** महोदय, उडुप्पी और अमरकंटक के लिए अलग अलग आपका एक्सपोजर क्या होगा?

**सतनाम सिंह :** उडुप्पी और लैंको अमरकंटक की बकाया ऋण राशि क्रमश: 1,325 करोड़ रुपए और 1,429 करोड़ रुपए है।

**महरुख :** महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। हमें अंतिम प्रश्न प्राप्त हुआ है जो जेएम फाइनेंसिंयल से अमय साथे की लाइन से एक अनुवर्ती प्रश्न के रूप में है। कृपया अपनी बात कहें।

**अमय साथे :** केवल एक प्रश्न। महोदय, पिछले 15-18 वर्ष में क्या ऐसा कोई मामला प्रकाश में आया है जहां आपको राज्य सरकार की किसी गारंटी को वास्तविक रूप से इस्तेमाल करना पड़ा हो?

**सतनाम सिंह :** नहीं, हमने राज्य सरकार की कोई गारंटी का इस्तेमाल नहीं किया है।

कांफ्रेंस कॉल ट्रांस्क्रिप्ट
06 अगस्त 2013

**अमय साथे :** धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। मैं सम्मेलन के समापन हेतु अंतिम टिप्पणियों के लिए श्री समीर नारंग को आमंत्रित करना चाहूंगा। महोदय, आगे आएं और माइक संभालें।

**समीर नारंग :** सभी प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंधन, विशेष रूप से श्री सतनाम सिंह, सीएमडी को हमें इस कॉन्फ्रेंस कॉल के प्रायोजन का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुन: धन्यवाद।

**मॉडरेटर :** धन्यवाद। प्रतिभागियों मैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस कॉल के समापन की घोषणा करता हूं। हमारे बीच उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आप अपनी लाइनें काट सकते हैं।

---

*नोट*: पठनीयता और उपयुक्तता में सुधार के लिए इस दस्तावेज का संपादन किया गया है।